

(17)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा०मधु खरे

### सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक १९५७-एक/२००५ - विरुद्ध आदेश दिनांक  
१६-८-२००५ - पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग,  
ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक १५०/१९९४-९५ अपील

घनश्याम पाठक पुत्र गुलाब चंद पाठक  
ग्राम राई, परगना कोलारस,जिला शिवपुरी

---आवेदक

### विरुद्ध

१- मान सिंह पुत्र नारायण

२- सीताराम पुत्र नारायण

दोनों निवासी ग्राम बेहटरा तहसील कोलारस

जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश

-- अनावेदकगण

(श्री डी०एस०चौहान अभिभाषक - आवेदक)

(श्री राजीव गौतम अभिभाषक - अनावेदकगण)

आ दे श  
(दिनांक ०४ दिसम्बर, २०१५)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक १५०/१९९४-९५ अपील में पारित आदेश दि. १६-०८-२००५ के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम बेहटरा स्थित आराजी क्रमांक २ रकबा ०.६४ एंव २६६ रकबा २.८९ हैक्टर पर पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक ने पटवारी हलका नंबर १८ तहसील कोलारस से

०१

नामान्तरण की मांग की। पटवारी द्वारा इस्तहार जारी करने पर आपत्ति आने से मामला विवादित होने के कारण तहसील न्यायालय को हस्तांतरित हुआ, जिस पर से तहसीलदार कोलारस ने प्रकरण क्रमांक 2/1989-90 अ-6 पंजीबद्ध किया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई 15-1-1994 पारित किया तथा व्यवहार उपरांत आदेश दिनांक 10.10.1992 के आधार पर आवेदक का क्य की पारित आदेश दिनांक 33/1993-94 प्रस्तुत होने भूमि पर नामान्तरण द्वीकार किया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष अपील क्रमांक 150/1994-95 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 20-1-1995 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 15-1-1994 तथा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस का आदेश दिनांक 20-1-1995 निरस्त किये गये तथा प्रकरण माना अपर जिला न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18-3-2005 के क्रम में कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी प्रस्तुत का गई है।  
3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ व्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 16-8-2005 में जिन आधारों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी कोलारस एंव तहसीलदार कोलारस के आदेशों को निरस्त किया है उनके द्वारा आदेश दिनांक 16-8-2005 में दिये गये निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि व्यवहार न्यायाधीश के आदेश दिनांक 10.10.1992 को अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांक 18-3-2005 से निरस्त करने का आधार लिया है जबकि अतिरिक्त

जिला एंव सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18-3-2005 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील क्रमांक 444/05 प्रस्तुत हुई है एंव आदेश दिनांक 8-4-2005 से स्थगन आदेश जारी हुआ है इसी आधार पर उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदकगण के अभिभाषक ने इसका विरोध कर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के आदेश को सही होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कोलारस के प्रकरण क्रमांक 26 ए/92 ई0दी0 में पारित आदेश दिनांक 10.10.1992 के आधार पर तहसीलदार कोलारस ने आदेश दिनांक 15-1-1994 से नामान्तरण किया है जबकि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कोलारस का आदेश दिनांक 10.10.1992 अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18-3-2005 से निरस्त हुआ है और इसी आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 150/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-08-2005 से अनुविभागीय अधिकारी कोलारस का आदेश दिनांक 20-1-1995 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-1-1994 निरस्त करके प्रकरण अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18-3-2005 अनुसार कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया है। माननीय उच्च न्यायालय से आदेश दिनांक 17-6-2014 को द्वितीय अपील क्रमांक 444/05 निरस्त होना अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताते हुये आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की है। वैसे भी तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस पहुंचने पर आवेदक को एंव अनावेदकगण को बचाव प्रस्तुत करने एंव लेखी/ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त रहेगा, जहाँ पर अनावेदक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 17-6-2014 को होना बताया गया है एंव अपर आयुक्त का

विचाराधीन आदेश 16-8-2005 का है। विचाराधीन निगरानी में अपर आयुक्त, ज्वालियर संभाग, ज्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 150/1994-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-08-2005 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है कि अपर आयुक्त के विचाराधीन आदेश के तारतम्य में कार्यवाही करते हुये विचारण व्यायालय उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत अद्वतन व्यायालयीन निर्णयों का सुचारू-रूप से अध्ययन कर प्रकरण का गुणदोषों के आधार पर निराकरण करें।

(डॉ.मधु खरे)  
सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ज्वालियर